

Notification of the Ministry of Finance

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification G.S.R. No. 664(E), dated the 22nd November, 1974, together with an Explanatory Memorandum thereon. [Placed in Library See No. L T 8581/74]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**Reported Collapse of a Suspension Bridge over river Mahakali**

श्री हर्षदेव मातवीय (उत्तर प्रदेश) श्रीमान, 17 नवम्बर, 1974 को भारत-नेपाल सीमा पर भारत का और महाकाली नदी के उपर झूला पुल के टूट जाने और उसके कारण 142 व्यक्तियों की, जिनमें अधिकांश भारतीय थे, मृत्यु हो जाने के समाचार की और मैं परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ।

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI) : Sir, according to the news-item that appeared in the Times of India and other papers on 27th November, 1974 over 140 persons, mostly Indians, have been reported missing following the collapse of the hanging rope bridge over the Mahakali River on the Indo-Nepalese border on November 17. This news-item states that eight persons on the bridge at the time of tragedy swam a shore, and four bodies were recovered.

This news-item has further given the information that there was heavy traffic on the bridge on that day because of the traditional Joola Jeevi fair held after Diwali in Darchula District of the Nepalese Kingdom which is attended by people on both sides of the border. It also mentions that the bridge gave way when pillars on the Indian side collapsed as the bridge could obviously not bear the weight of about 150 persons.

The Survey of India Map shows that the River Mahakali flows along the Indo-Nepal border dividing Pithoragarh District of U.P. and the Nepal Kingdom. The bridge does not fall on any National Highway system in the country.

In this connection, the following telex message was received by the Ministry of External Affairs (Government of India) from the Government of U.P. on 18th November, 1974 :

"D.M. PITHORAGARH HAS INFORMED THAT SUSPENSION BRIDGE AT JAULJIBI OVER RIVER KALI AT INDO-NEPAL BORDER COLLAPSED AT 1215 HRS ON 17 NOV. WHICH WAS THE THIRD DAY OF FAIR. 17 PERSONS RESCUED FROM RIVER. CASUALTIES SUSPECTED INTENSIVE SEARCH FOR SUSPECTED MISSING PERSONS BEING MADE. FIRST AID GIVEN TO THOSE INJURED. BRIDGE IS MAINTAINED BY NEPAL GOVERNMENT. COMMISSIONER KUMAR HAS ALSO BEEN ASKED TO VISIT JAULJIBI IMMEDIATELY."

The Ministry of External Affairs have also contacted the Minister in the Embassy of India, Kathmandu, regarding further details of the accident. They have reported that the Indian News report appearing in the Times of India on 27th November datelined Kathmandu, November 26, appears to be based on a news item in the 'Rising Nepal' of the 26th November, an official newspaper of the Govt. of Nepal and that the Embassy has asked for further information from the Govt. of Nepal, who in turn, have asked the District authorities to give detailed report on the accident.

The U.P. Government is also being contacted by this Ministry to get further details of the accident. After the full details of the accident are available from the U.P. Government and the embassy of India in Nepal, the same would be placed before the House.

श्री हर्षदेव मातवीय : मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमको बताया उससे यह पता लगता है कि यह अभी तक सुनिश्चित नहीं है कि यह हादसा जो हुआ उसमें कितने लोग मरे। उसका विस्तृत विवरण अभी पता नहीं हुआ है। वाक्या हुआ 17 नवम्बर को और आज 28 नवम्बर है, काफी दिन बीत गये, तो यह जरा सा सोचने की बात है कि इतने बड़े हादसे के बाद इतनी देर में समाचार हमको क्यों नहीं प्राप्त हुए ?

दूसरी बात में जानना चाहता हूँ कि यह पुल कब बना था ? कितने साल हो गये ? और जो यह पुल है यह केन्द्रीय सरकार की देखरेख में है अथवा यह प्रादेशिक सरकार की देखरेख में है ? उस पुल की क्या कभी कोई

[श्री हर्षदेव मालवीय]

जांच पड़ताल होती है ? क्या यह देखा गया कि वह पुल खराब है, भरम्मत की जरूरत पड़ती है, और यह कार्यवाही हुई या नहीं ? जो सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आती वह यह है कि यह भारत की साइड में क्यों टूटा, नेपाल में क्यों नहीं टूटा ? पुल से 140 आदमी गिर पड़े, पता नहीं कुल कितने थे । आप जानते हैं, मान्यवर, कि जब प्रयाग में कुम्भ मेला होता है तो लाखों करोड़ों आदमी आते हैं । वहां पर जो फानटून ब्रिज है या दूसरे ब्रिज हैं सबकी सरकार की तरफ से अच्छी जांच पड़ताल कर ली जाती है कि कोई कमजोरियां तो नहीं हैं । कोई कमजोरी होती है तो वह ठीक कर ली जाती है । यह जेलजीवी का जो मेला है वह हर साल लगता है । लाखों आदमी वहां जाते हैं, भारत और नेपाल में । तो हम जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जांच की कार्यवाही उस पुल की हुई थी कि नहीं हमारे भारत की दिशा में जो हिस्सा पड़ता है वही क्यों टूटा ?

इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि हमारे देश में ठेकेदारों का धपला चला करता है । इस पुल में कहीं ठेकेदारों का धपला तो नहीं है, इस बारे में सूचना हो तो बताये । यदि कोई ठेकेदार या बनाने वाला या जो भी आदमी हों, इसके लिये जिम्मेदार है तो क्या सरकार उसका पता लगा करके उसको सजा देगी या नहीं ?

अंतिम सवाल मेरा यह है कि जो बेचारे मर गये उनको कुछ मुआवजा, कंपेंसेशन वगैरह देने के लिये सरकार सोचती है कि नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, जो पहला प्रश्न है कि यह पुल कब बना था, उसकी मुझे सूचना नहीं है कि कब का बना हुआ पुल है ।

दूसरी बात यह कि इस पुल के रखरखाव, इसकी भरण-रक्ष, इसका इंतजाम, सारा इसका प्रबन्ध हमारे हाथ में नहीं है, नेपाल सरकार के हाथ में है । न भारत सरकार के हाथ में है, न यू०पी० सरकार के हाथ में है । लिहाजा इसको देखना कि इसकी भरण-रक्ष और इसका रखरखाव ठीक से होता है या नहीं, इसका प्रश्न उठता नहीं ।

तीसरी बात यह है कि भारत की ओर ही यह क्यों गिरा । अब चाहे इधर गिरता, चाहे उधर गिरता, गिरना दुर्भाग्य की बात है । अगर उधर गिरा होता और आदमी उससे मरे होते तो भी दुरा होता और इधर गिरा आदमी मरे तो भी दुर्भाग्यपूर्ण है ।

श्री हर्षदेव मालवीय : पंडित जी ऐसा तो नहीं है कि नेपाल ने रखरखाव अपनी तरफ का किया हो, भारत दिशा की तरफ छोड़ दिया हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मालूम होता है कि इस इलाके से लोग जा रहे थे, जैसी सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार 150 आदमी थे वह बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सका । उसके पिलस गिर गये । उसमें काफी आदमी मरे हैं । ऐसा लगता है कि 8 आदमी तैरकर किनारे आये, बाकी की खोज की जा रही है और जो तार मिला था पिठौरा-गढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उसमें मालूम होता है कि बहुत कैजुएल्टीज हुई है ।

यह सही है कि घटना घटी 17 तारीख को और 27 तारीख तक हमें इसका पता नहीं लगा । यह बात भी सही है कि हम को पता लग जाना चाहिये था । 18 तारीख को ही । पिठौरागढ़ के मजिस्ट्रेट ने तार दे दिया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को । इस मिनिस्ट्री से पूछताछ की है जैसा कि ब्यान से मालूम होता है ।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कब खबर दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : 18 तारीख को ।

श्री राजनारायण : घटना कब घटी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : घटना घटी 17 तारीख को लेकिन यहाँ अखबार में छपा 27 को । यह सवाल आपने पूछा कि 18 या 17 को जो घटना घटी उसकी सूचना 26 तारीख तक हम को क्यों नहीं मिली । मैं कह रहा था कि उसकी सूचना मिल गई थी । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 18 तारीख को तार भेज दिया था । लेकिन चूंकि नेपाल गवर्नमेंट के हिस्से में पड़ता है यह पुल और रख-रखाव भी उनके जिम्मे है हमारा तो केवल बॉर्डर ही है इसीलिये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पूछताछ की नेपाल सरकार से । अपनी असेम्बली को भी लिखा और उन्होंने भी वहाँ से पूछ-ताछ की । वहाँ उन लोगों ने इतनी खबर दी है कि अभी हम इसकी जांच करके इसकी खबर देगे । 'राइजिंग सन' नेपाल से एक अखबार निकलता है उसमें यह खबर 26 तारीख को छपी थी और उसकी बुनियाद पर 'टाइम्स आफ इंडिया' ने छपा जिससे आप को पता लगा । वैसे यह घटना 17 को है तब से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बराबर पूछ रही है । यू०पी० गवर्नमेंट से भी पूछताछ की है । उन्होंने कहा है कि खबर लेकर आप को बता देगे । ज्योती प्रा समाचार आयोग । एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिये हम उसे प्राप्त कर लेगे और फिर सदन के सम्मुख रख देगे ।

श्री हर्षदेव मालवीय : जो मरे है उनको मुआवजा मिलेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : पहल तो यह पता लगे कि मरे कौन हैं और कितनी संख्या में मरे हैं । मुआवजा

भारत सरकार देगी, उत्तर प्रदेश सरकार देगी या नेपाल सरकार देगी यह प्रश्न टेढ़ा है।

श्री राजनारायण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह पुल उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर है और नदी के एक किनारे पर है। यह सरकार का कहना कैसे उचित माना जायेगा, सरकार इसको क्यों कह रही है और सरकार को यह कहने की आप क्यों इजाजत दे रहे हैं कि यह एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का मामला क्यों नहीं है, आपके विभाग का मामला क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार कान और नाक में तेल डाले क्यों पड़ी हुई है। 142 लोगो की जान चली गई और वहां पर सरकार की ओर से कोई उदासीनता न हो, यह कैसे उचित माना जा सकता है। कमलापति जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वही के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, श्रम मंत्री रह चुके हैं...

MR. CHAIRMAN : That will be kept in view. Let the hon. Member put his question.

श्री राजनारायण : मेरा कहना यह है कि मंत्री जो उत्तर दें वह तो उचित होना चाहिये।

MR. CHAIRMAN : That is all right.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Firstly, I would like to know why the hon. Minister took the responsibility of replying to this question when it was entrusted to him because it does not come under his jurisdiction in any shape.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

He should have categorically told the Rajya Sabha Secretariat that it does not pertain to him and whosoever is the Minister-in-charge of it in the External Affairs Ministry should take the responsibility to reply to these questions. There must be a procedure and I do not know whether the hon. Minister would be in a position to say that because it is only the External Affairs Ministry which can reply. I am happy that the Deputy Minister of External Affairs is here and so he should reply to the question. He must have been briefed about it or else there is no occasion for him to be here..

SHRI D.N. DWIVEDI (Uttar Pradesh) : He is a Member of this House.

SHRI LOKANATH MISRA : Some people try to show their wisdom by bringing to the notice of the House that a particular Minister is a Member of this House. It does not add to the wisdom of anybody.

SHRI D. N. DWIVEDI : It was relevant and that was why I brought it to your notice.

SHRI LOKANATH MISRA : Ministers belong to both Houses. Therefore, it is not the privilege of this House to own him because you cannot own him all the time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You ask your clarification.

SHRI LOKANATH MISRA : I wanted to know what is the procedure in the case of a particular river as Mahakali which happens to be the border river between two countries and how such bridges which connect two countries are maintained in the normal course. If it is being maintained by the Nepal Government, then there must have been some kind of an agreement between India and Nepal as to who would be responsible for the maintenance of it or who would be looking after it. Or is it also the partial responsibility of the Government of India to supervise, through its officers, the use of the bridge by a particular number of persons at a time? Was any notice hung there that this is the capacity that the bridge can carry and that beyond that nobody should get on to the bridge? If such caution notices were not there, whether it is the Nepal Government or the Indian Government—as indicated by our socialist friend from there who has now disappeared, whether it is this Government or the other Government—somebody must be held responsible for paying compensation. If it was the responsibility of the Nepal Government to look after the bridge and if nothing has been notified there near this bridge that this is the capacity of the bridge and that nobody should go beyond that capacity, then the Nepal Government becomes responsible for it, and it is for the External Ministry now to demand compensation from them.

Now, Sir, finally, the question has been relegated to fate by the hon. Minister by saying that it did not collapse on the other side but that it collapsed from this side. We cannot relegate these things to fate alone when we function in a Government, and as part of the Government, the hon. Minister will have to say something to justify the functioning of the Government as to how it collapsed. Eleven days have passed, and some kind of an inquiry must have been started by the Government of UP or by the Government of Nepal as to what was the reason for this collapse, how it collapsed

[Shri Lokanath Misra]

There must have been some case history behind it, some case history must have been collected about it. Will the hon. Minister kindly let us know as to the reason of the collapse. And I hope that you, Sir, would kindly ask the Deputy Minister of External Affairs to apprise this House of it, or else it is a futile exercise, the entire exercise would be a futile one. And when you do not get answers, why ask questions at all ? It is only a waste of time.

SHRI BIPINPAL DAS (Assam) : It pertains to both Ministries.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI : This motion was called by the hon. Member in my name and this was admitted by the Chairman in my name. So, I think...

SHRI RABI RAY (Orissa) : You are not the Minister in charge of that thing.

SHRI LOKANATH MISRA : I do not accuse the hon. Minister. On a point of personal explanation, as private Members, we do not know whether the bridge is maintained by us or by the Nepal Government or jointly or whether it belongs to the UP Government or to somebody else....

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI : You are perfectly right.

SHRI LOKANATH MISRA : We may be ignorant about it as private Members. But it is collective responsibility.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is why he is answering.

SHRI LOKANATH MISRA : If we had sent notices in the wrong name, the Department or the Ministry should have sent it on to the relevant Ministry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has collected the information and he is giving it.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI : There is nothing wrong if I have also answered this Calling Attention Notice, and I think the hon. members should be grateful and thankful to me that I have come to their rescue.

As soon as we came to know this, we have contacted the U.P. Government also for full details. And the External Affairs Ministry has also contacted our Embassy in Kathmandu.

SHRI LOKANATH MISRA : What is their report ?

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI : Their report was the telex message that we received from the District Magistrate of Pithoragarh ..

SHRI LOKANATH MISRA : The External Affairs Ministry does not deal with District Magistrates.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI : They say that the Embassy has asked for further information from the Government of Nepal who, in turn, have asked the District authorities to give detailed report on the accident. As soon as we get the detailed report, we shall place it before the House.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उप-सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जो बात कही है, पहले तो इस विषय में पौड्यस्ट आफ आर्डर ही आपके सामने उठाना चाहूंगा और वह यह है कि मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं पहले तो उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि इस पुल का पूर्ण उत्तरदायित्व नेपाल सरकार के हाथ में है और हमारे विदेश मंत्रालय को सूचना मिली है कि दूतावास के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि यह विषय आपका है ही नहीं और जानकारी अगर हम चाहें भी तब भी आप उसको देने में अभी तक असमर्थ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी की गलती से भी अगर आपको बोल दिया गया है उत्तर देने के लिये तो क्या आप अपनी रुढ़िगत देगे कि इस काल अटन्शन मोशन को विदेश मंत्रालय के नाम ट्रांसफर करके दूसरे दिन के लिये स्थगित किया जाये...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, he is quite competent to answer the question. He is collecting information from the External Affairs Ministry.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : क्लेवट ही नहीं कर सकते।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Tyagi, you cannot have it both ways. You cannot, on the one hand say that it is collective responsibility and, on the other, say he cannot collect information. Now, please ask for clarifications.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : उपसभापति महोदय, देखिए मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूंगा और वे फौरन कहेंगे विदेश मंत्रालय जानता है। मैं अभी यह

जानना चाहूंगा कि यह जो पुल है इस पर 142 आदमी और वे सब भारतीय मरे हैं और उनके कितने ही आदमियों के परिवार उजड़ गये हैं। इसलिये आप इस विषयों को उतनी आसानी से नहीं ले सकते। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह जो पुल है इसका निर्माण कब किया गया था। मंत्री महोदय जरा मुन लेंगे कि कोई भी पुल जो सरकार की ज़िम्मेवारी पर होता है उसकी विशेष आयु होती है; उस विशेष आयु के पश्चात् उस पुल को या बिगडिंग को समाप्त कर दिया जाता है और दूसरा पुल बनाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फौरन आपसे यह जानकारी प्राप्त की कि इस पुल की आयु कितनी थी और क्या उस आयु से ज्यादा यह पुल चलता रहा और नेपाल सरकार ने कोई इस प्रकार का ध्यान दिया नहीं क्योंकि इस पर ज्यादातर यात्रियों का, खास कर भारतीयों का, आना जाना रहता रहा है। नेपाल सरकार ने लापरवाही की और उस आयु के बाद में भी उस पुल को चालू रखा गया है। तो क्या यह एक कारण तो नहीं है, इस बारे में आपसे पहली जानकारी चाहूंगा।

दूसरी बात, यह जानकारी चाहूंगा कि क्या नेपाल सरकार ने अपनी भी कोई जांच समिति बैठाई है या नहीं बैठाई? क्या जब यह पुल हमारी सीमा में भी आता है तब का यह किनारा हमारी सीमा में है, उत्तरदायित्व हमारा भी है? क्या सरकार अपनी ओर से भी कोई जांच कमेटी बैठाएगी ताकि पुल के गिरने के कारण का पता लगे और ये जो इतने आदमी मरे इसमें किसकी रिसपॉन्सिबिलिटी थी, किसकी नहीं। जैसा लोकनाथ मिश्र जी ने कहा इस पुल की कैपेसिटी कितनी थी, इस तरह की वॉनिंग थी या नहीं? तो इस प्रकार की पूरी जांच आप अपनी ओर से करायेगे, उसके लिये कोई कमेटी नियुक्त करेंगे या नहीं?

तीसरी बात जो मुझे पूछनी है वह कम्पेसेशन की बात है। आपने कहा, भारत सरकार देगी। अगर पूर्ण उत्तरदायित्व नेपाल सरकार का है उस पुल के ऊपर जिसके कारण यात्री मर गये, और वह नेपाल की सीमा में थे, नेपाल में उनकी मृत्यु हुई है, नेपाल सरकार ने उनको अपने यहाँ आने की अनुमति दी और उनकी वहा देवी के मेले पर जाने की बात थी, इसलिये जो कम्पेसेशन है, मुआवजा है, क्या भारत सरकार उनका मुआवजा नेपाल सरकार से मांगेगी या नहीं? मैं सीधा उत्तर पूछ रहा हूँ, कौन मांगेगा? यह नहीं कि भारत सरकार देगी, क्योंकि वे नेपाल की सीमा में मरे हैं और उस पुल पर मरे हैं जिसका उत्तरदायित्व आप के दृष्टिकोण से पणत नेपाल सरकार पर था। इसलिये उनकी मृत्यु का दायित्व नेपाल सरकार पर आता है। तो क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार से इस बारे में मुआवजा मांगा या नहीं? अगर भारत सरकार इतनी दयालु है कि वह कोई मुआवजा नेपाल सरकार से नहीं

मांगती है, तो भारत सरकार को मुआवजा देने का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये।

अन्तिम प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में यह बात खोजने की है और जांच बिठलाने की है कि भारत सीमा की ओर जो पुल का हिस्सा गिरा, स्वाभाविक है कि वह गिरना था, लेकिन नेपाल के साथ हमारे जिस तरह के संबंध हैं, उन संबंधों को बिगाड़ने के लिये कोई विदेशी एजेंट तो काम नहीं कर रहे हैं? तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस कार्य में आपको सेबोटेज दिखलाई देता है और इस बारे में सदेह है? मैं यह मांग करता हूँ कि इस बारे में भारत सरकार एक जांच कमेटी बिठलाये ताकि इन सब बातों पर प्रकाश मिल सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी मान्यवर, मैं समझता हूँ कि नेपाल हमारा एक मित्र देश है और हमारी उनकी मंत्री है तथा अच्छे संबंध हैं। इस सदन में इस तरह के प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहिये और विशेषकर उस देश के संबंध में जो कि हमारा एक मित्र देश है और जिसमें हम मित्रता के सूत्र में बंधे हुए हैं।

श्री राजनारायण : उन्होंने तो किसी देश का नाम ही नहीं लिया और न उसके बारे में इस तरह की कोई बात कही।
(Interruption).

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He can always express an opinion.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं आप से यह कह रहा था कि हमें इस तरह की कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे हमारे मित्र देश को किसी तरह की कोई ठेस पड़वे। मैं ने तो सिर्फ यही कहा कि हमें ठेस पड़वाने वाली बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Tyagi you must be fair to him. Before he completes a sentence, you are getting up.

श्री राजनारायण : जब इस बारे में तथ्य मालूम न हों, तो सरकार को इस बारे में बतलाना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं आपका कारण बतला रहा हूँ।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : जो बात मैंने कही है, उस पर आप मेरे ऊपर कह रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has not said that. Let him answer.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मेरा निवेदन यह है कि आप मेरी बात सुन ले और उमके बाद जो कुछ कहना चाहें कहें। मेरा निवेदन यह है कि इस सत्र में अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि उस घटना में क्या हुआ। हम यह भी नहीं जानते हैं कि इस घटना में कितने लोग मरे और जितने भी मरे वे नेपाल की सीमा में मरे या हिन्दुस्तान की सीमा में मरे? ये लोग किस तरह से मरे, क्या पुल कोलेम्प हुआ, तब मरे, इस बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। जैसा मैंने आप से निवेदन किया है कि हमने इस बारे में यूपी० की सरकार से और नेपाल में अपने राजदूत से रिपोर्ट मांगी है। जब वह रिपोर्ट आ जायेगी तो उसको सदन के सामने रख दिया जायेगा। इस वक्त यह कह देना कि जॉ लोग मरे हैं, वे नेपाल की सीमा पर मरे हैं और नेपाल सरकार से कम्पेन्सेशन मांगा जायेगा या नहीं मांगा जायेगा, इस समय यह अच्छा नहीं होगा। इस तरह की बातों से दो देशों की मित्रता में बाधा पहुँच सकती है।

आपने जितने सवाल किये हैं, उनका उत्तर मैं इस समय नहीं दे सकता हूँ कि कितने लोग मरे हैं, इस पार मरे हैं या उस पार मरे हैं, ब्रिज कोलेस हुआ, इन मारी बातों का जवाब जब हमारे पास रिपोर्ट आ जायेगी तब ही दिया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि यह रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी और जैसे ही आयेगी उसकी सूचना सदन को दे दी जाएगी।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने यह बात स्वीकार की है कि इस ब्रिज का उत्तर-दायित्व नेपाल सरकार के ऊपर है। वे कहते हैं कि इस पुल के गिर जाने से इतने भारतीय लोग मर गये हैं और इसका मतलब यह होता है कि नेपाल की सीमा पर ये लोग मरे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has answered this point. I am calling Shri Banarsi Das.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैंने विशेष रूप से पूछा था कि इस घटना के बारे में कोई जांच कमेटी बिठलाई जायेगी?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has answered this. If he had not answered, I would have permitted you. Shri Banarsi Das.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैंने यह पूछा कि क्या भारत सरकार अपनी ओर से कोई जांच कमेटी बेंजाने का विचार करती है; यदि नहीं तो क्यों? इसका जवाब दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी : जांच कमेटी का प्रश्न नहीं उठता, न उस पर विचार किया जा सकता है जब तक कि रिपोर्ट न आ जाये।

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि 11 दिन इस दुर्घटना को हो गये, जिसमें 142 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार प्रकाशित हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार को निश्चयात्मक रूप से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई कि कितनी मृत्यु हुई। साथ ही मंत्री जी का यह उत्तर देना कि क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, भारत सरकार की है या नेपाल की सरकार की है यह अभी नहीं कहा जा सकता, यह उत्तरदायित्व को नहीं मानता है। यह पुल नेपाल सरकार के रखरखाव में है। क्या कोई इंटरनेशनल एग्जामेंट ऐसा नहीं है कि यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस प्रकार के अनेक पुल हैं जो हमारे और नेपाल के बीच में हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इस बात की घोषणा करें कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको कम्पेन्सेशन उत्तर प्रदेश सरकार देगी, चाहे फिर उनको रिकम्पेन्सेट भारत सरकार करे या नेपाल सरकार करे। यह कितनी बड़ी उदासीनता और उपेक्षा का विषय है कि नेपाल के अन्दर हमारी फूल फूलेज्ड एम्बेसी है, लेकिन अभी तक वह इतनी बड़ी दुर्घटना की सूचना भारत सरकार को नहीं दे सकी? क्या यह उनकी कार्यक्षमता की कमी नहीं है? जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है क्या यह उदासीनता उनके परिवार के साथ निर्ययता नहीं है? मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वे कम्पेन्सेशन की घोषणा करें और साथ ही साथ जब सदन 2 तारीख को बैठे तो एम्बेसी का उत्तर लेकर पूर्ण विवरण वे सदन के सामने पेश करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, बारबार वही सवाल आ रहे हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि घटना 17-18 तारीख की है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ के जरिये उत्तर प्रदेश सरकार को उनके जरिये एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री को इसकी सूचना मिली। 26 तारीख को टाइम्स आफ इंडिया में निकला जिसमें यह प्रश्न उपस्थित हुआ।

श्री राजनारायण : सरकार को कब खबर मिली?

श्री कमलापति त्रिपाठी : 18 तारीख को पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश सरकार को और उन्होंने एक्सटर्नल एफेयर्स को टेलीग्राम भेजा कि यह घटना घटी उसी वक्त से उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी और लिखना शुरू कर दिया अपनी एम्बेसी को, वहाँ के डिपार्टमेंट्स को।

श्री बनारसी दास : आपके मंत्रालय को सूचना एक्सटर्नल एफेयर्स ने कब दी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी : जब से आपने सवाल किया है मेरा मंत्रालय सूचना इकट्ठा करके आपको दे रहा है।

श्री राजनारायण : हमारा एक व्यवस्था का मवाल है। सरकार क्यों कहती है कि हमको 26 तारीख को खबर मिली जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ने 18 तारीख को ट्वेलेक्स भेज दिया था। सरकार को कहना यह चाहिए था कि सरकार के एक्सटर्नल विभाग को 18 को ही जानकारी हो गई थी, लेकिन चूँकि तमाम प्रमुख मंत्री लोग नरौरा गए हुए थे, बुलन्दशहर, कांछी के आन्तरिक इगडो को निपटाने के लिये इसलिये सरकार के पास फुरसत ही नहीं थी कि इनने अहम मामले पर सरकार विचार करती। गलन उतर क्यों देते हैं ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has been saying that they got the information on the 18th.

श्री बनारसी दास : उपमभाषित महोदय, मैं आपके द्वारा एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मंत्री जी को आदेश दे कि वे इतनी तो धोषणा करें कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को अवध कम्पेंसेशन दिया जायेगा। कौन सरकार देगी यह अलग बात है। असंगत है।

श्री श्री प्रकाश त्यागी : अभी मंत्री जी का यही नही मानूँ कि मरे या नहीं।

श्री राजनारायण : यह तो वे जानते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मंत्री को पता तब लगता है जब रिपोर्ट आती है। आपको पता नहीं लगा जब अखबारों में छपा। यही हमेशा का तरीका है कि जाच-पड़ताल करने के बाद जब कम्पलीट रिपोर्ट आ जाए तो आपके सामने रखी जाए। कम्पेंसेशन की बात यह है कि सारी धटनाओं में हमेशा कम्पेंसेशन नहीं दिया जाता। यह धटना ऐसी है जिसमें कम्पेंसेशन दिया जाये या न दिया जाये, यह रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जा सकता है। तभी यह सोचा जा सकता है कि अगर कम्पेंसेशन देना है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है या कहीं और आती है।

श्री बनारसी दास : यह सरकारी पुल है, और गवर्न-मेंट का पुल है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को पहले पूरा उत्तर सुन लेना चाहिये, फिर उसके बाद प्रश्न करना हो तो करे। उत्तर यह है कि इस पुल का रख रखाव नेपाल सरकार के ऊपर है। हमारे पास यह रिपोर्ट नहीं है, जैसा अभी त्यागी जी ने कहा कि जब पुल टूटा तो कोई न कोई लोग नेपाल के एरिया में गिरे होंगे। यह नदी है अगर तो मान लीजिये कि बाँडर पर नदी है तो ऐसा भी हो सकता है कि नदी का कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में हो और कुछ उनके हिस्से में हो। जब तक पूरी रिपोर्ट न आ जाए हर बात की तब तक निश्चित रूप

से नहीं कह सकते कि मरने वालों की तादाद कितनी है, पुल किस बजह से टूटा, किसके बाँडर में लोग गिरे मरे। सारी रिपोर्ट आने के बाद जब सदन में पेश कर दी जायेगी तो उसके बाद हम पर विचार हो सकता है। नेपाल सरकार की कार्यक्षमता की अगर यहाँ आलोचना करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि वह मुनासिब नहीं होगा। नेपाल से हमारे संबन्ध बहुत स्नेह और मित्रता के संबंध है। वहाँ के आफिसरों और विभाग की कार्यक्षमता की आलोचना न कर।

हम यह जानते हैं कि इसका पता हम को जल्द से जल्द लगना चाहिए था, पता नहीं लगा, यह दुर्भाग्य की बात है। जब 18 तारीख को खबर आई तो हमने ऐम्बेसी से पूछा तो वहाँ से उत्तर आया कि नेपाल सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से पूछा है। यू०पी० गवर्नमेंट को हमने लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ से पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वह सदन में पेश कर दी जायेगी।

श्री राजनारायण : सारा दुर्भाग्य नरौरा सम्मेशन का है, उसी ने गड़बड़ किया है।

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : Sir, I am ready to wait till the report is available, because I know the communications system in Nepal; it takes some time to collect information. But I would like to know only one thing. Does it form part of the border road system which we have built recently? That is number one. Secondly, I was told that a new type of bridge, which can be built very quickly, has been in use in that area. Does this particular bridge belong to that type? Perhaps it was not properly tested and, therefore, it collapsed. Have you any idea whether this bridge belongs to the new type of bridges that we put up there for quick transportation and whether it is in the sector of border roads?

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI : Sir, unless I get the report, I can not say what type of bridge is there. We cannot know unless we get the report whether this is a new bridge or an old bridge. It is a bridge neither on the national highways nor on the border road.

REFERENCE TO ASSAULT ON SHRI JAYAPRAKASH NARAIN

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Special Mention. Mr. Prakash Vir Shastri.